हांगकांग और आजादी का भविष्य

ब्रेट स्टीफेंस

© The New York Times 2019

नया प्रत्यर्पण कानून हांगकांग में चीन की तानाशाही का ताजा उदाहरण है। हांगकांग पर चीन की यह दमनकारी नीति क्षुब्ध तो करती है, लेकिन उतना ही आश्चर्यजनक यह है कि ट्रंप इस पर चुप हैं, जबकि बीजिंग का रवैया 1984 की चीन-ब्रिटेन घोषणा का सरासर उल्लंघन है। लोकतंत्र की मुश्किलों और राष्ट्रवाद के उभार के बीच यही हो सकता है।

इसकी कल्पना करें कि ट्रंप प्रशासन ने अगर 2018 में ऐसा कोई कानून बनाया होता, जिसके तहत सरकार के पास ऐसे किसी भी अमेरिकी को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार होता, जो संदिग्ध अवस्था में अश्वेतों की आबादी के आसपास मंडराते पाए जाते, तो क्या होता। यह भी कल्पना करें कि अमेरिकी उस कानून का विरोध करते, लेकिन बदले में उनका सामना आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से होता, तो क्या होता। और अंत में यह भी कल्पना करें कि अमेरिका में उस कानून को रोकने और संविधान की भावना को बचाए रखने के लिए प्रभावी न्यायपालिका नहीं होती, तो क्या होता।

हांगकांग में इस सप्ताह यही हुआ। लगभग दस लाख लोग उस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जो स्थानीय अधिकारियों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने और चीन में प्रत्यर्पित करने का अधिकार देता है, जो कुल 37 तरह के अपराधों में से किसी एक को अंजाम देता है। हालांकि राजनीतिक अपराध को इस सूची में नहीं रखा गया है, लेकिन हांगकांग के लोग इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि चीन की चालाकी न समझ पाएं। राजनीतिक विरोधियों

ताजा रित्पर्यण कानून चीन के दमनकारी शासन का ताजा उदाहरण है, हालांकि यह हांगकांग में उसकी तानाशाही का आखिरी उदाहरण नहीं है। चूंकि बहुलतावाद को बीजिंग अपने लिए खतरा मानता है, इसलिए वह ऐसी कोई गुंजाइश नही छोड़ना चाहता, जिससे हांगकांग को लगे कि वह स्वतंत्र है और अपना शासन खुद चला सकता है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने जब तत्कालीन सोवियत संघ को 'आधुनिक विश्व की बुरी ताकत' कहा था, तब एक चर्चित उदारवादी लेखक ने उनकी घोर आलोचना करते हुए उन्हें आदिम कहा था। रीगन की आलोचना ने तब उनके विरोधियों और सपने देखने वालों को नई ताकत दे दी थी। तब के मुक्त विश्व की आज की दुनिया से तुलना करें, तो निराशा होती है। विगत बुधवार को पोलिश राष्ट्रपति एंड्रजेज द्यूजा के साथ बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में हुए आंदोलन पर बस इतना कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, वे इस संकट से खुद को बाहर निकाल ले जाएंगे। ट्रंप और द्यूजा, दोनों नए राष्ट्रवाद के चैंपियन हैं, जिसका एक सिद्धांत यह है कि आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करो, तो दूसरे भी आपके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ट्रंप ने इस सिद्धांत का अब तक खूब इस्तेमाल किया है, चाहे वह सऊदी अरब का अपने संजीदा और स्टैंड लेने वाले पत्रकारों के साथ सुलूक रहा हो या उत्तर कोरिया का सभी के प्रति आक्रामक व्यवहार।

हांगकांग में नागरिक अधिकारों पर खुलेआम जिस तरह डाका डाला गया, उस पर ट्रंप ने कुछ ठोस क्यों नहीं कहा? क्योंकि ट्रंप को लगता है कि यह चीन का घरेलू मामला है। हांगकांग से संबंधित चीन का ताजा फैसला 1984 के ब्रिटिश-चीन साझा घोषणा का उल्लंघन है। इसके बावजूद ट्रंप चुप क्यों रहे? इसलिए कि उन्हें लगता है, यह उनका काम नहीं है, और 1984 की उस घोषणा का मसौदा तैयार करने वाले लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि शी जिनपिंग बाहरी देशों की परवाह किए बगैर हांगकांग के मामले में जो चाहे फैसला कर सकते हैं।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हांगकांग को उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। जैसा कि विलियम मैकगर्न ने *वॉल स्ट्रीट जर्नल* के अपने कॉलम में लिखा, चीन का ताजा कदम कानून का पालन करने वाले लाखों हांगकांग वासियों को चीन का विरोधी बना देगा। यानी हांगकांग में चीन के विरोधियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। लोकतंत्र को भले ही गलत नेतृत्व मिल जाए, लेकिन उसके पास तानाशाही व्यवस्था को शर्मसार करने का नैतिक विकल्प तो हमेशा रहेगा। तानाशाही सत्ता के पास यह विकल्प नहीं होता। लचीला न होने के कारण वह लोगों के लिए डरावना तो है, लेकिन उसके टूटकर बिखरने का खतरा भी है। आज पूरी दुनिया लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन देखने के लिए अभिशप्त है। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की अज्ञानता ने इस पूरे परिदृश्य को और भी दयनीय बना दिया है। लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली। चीन अपनी जिस तानाशाही पर गर्व करता है, और जो उसके वैश्विक उत्थान का कारण है, उसकी कलई भी खुल गई है- इतना ताकतवर एक देश उन लोगों से डर रहा है, जो हांगकांग की सड़कों पर उसके तानाशाही तौर-तरीके के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

डेविड डी किर्कपैट्रिक

© The New York Times 2019

ओमान में टैंकरों में हुए धमाकों का राज क्या है

ओमान की खाड़ी में बृहस्पतिवार को दो व्यावसायिक टैंकरों में हुए रहस्यमय धमाकों के बाद जहां तेल की कीमतें बढ सकती हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

हालांकि दोनों जहाजों को बिना किसी गंभीर नुकसान के खाली करवा लिया गया, लेकिन इस घटना ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ताकतों के बीच सैन्य विवाद बढ़ने का अंदेशा पैदा कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव तीन दशक में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं ईरान का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। क्या दो जहाजों पर हुए ये धमाके दुनिया को किसी खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं? जरा इस पर गौर करते हैं।

ये धमाके, जिन्हें अमेरिका ईरान द्वारा जानबूझकर किया गया हमला बता रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है। ओमान की खाड़ी फारस की खाड़ी में होर्मुज के 21-मील-चौड़े जलडमरूमध्य से गुजरती है, और दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग एक तिहाई और प्राकृतिक गैस का लगभग पांचवां हिस्सा इसके पानी से गुजरता है।

ये धमाके, जिन्हें अमेरिका ईरान द्वारा जानबूझकर किया गया हमला बता रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है। जहां धमाके हुए, दुनिया का एक तिहाई तेल इसी जलमार्ग से गुजरता है।

एशिया की ओर जा रहे दोनों जहाजों का अमेरिका से कोई संबंध नहीं था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वाशिंगटन फारस की खाड़ी से पेट्रोलियम का सुरक्षित निर्यात सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताता आया है। और 1990-91 में पहले खाड़ी युद्ध के बाद से अमेरिका ने इस क्षेत्र में सैन्य जमावड़े के जरिये अपनी इस प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इसलिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने या तेल के प्रवाह को रोकने के प्रयास से अमेरिकी हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा, भले ही इसमें कोई भी अमेरिकी जहाज शामिल न हो।

इसके अलावा ट्रंप ने ईरान से टकराव को प्राथमिकता में रखा है, जो कि इस्राइल और अरब की खाड़ी के देशों की शिकायतों के अनुरूप ही है कि तेहरान इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। ट्रंप ने पिछले वर्ष अमेरिका को 2015 में हुए उस समझौते से अलग कर लिया जिसमें ईरान को परमाणु कार्यक्रम में कटौती के एवज में आर्थिक लाभ देने का वादा किया गया था। उन्होंने न केवल पुराने प्रतिबंध बहाल कर दिए हैं, बल्कि कुछ नए प्रतिबंध भी लाद दिए हैं, जिससे ईरान की दुनिया में कहीं भी तेल निर्यात करने की क्षमता ध्वस्त हो जाए। उन्होंने ईरान की सेना का हिस्सा रिवोल्यूशनरी गॉर्ड को आतंकी गुट करार दिया है और धमकी दी है कि यदि ईरान अमेरिका से लड़ाई करता है तो वह बर्बादी लाने वाला बदला लेंगे। ट्रंप ट्वीटर पर ईरान के आधिकारिक रूप से खात्मे की बात लिख ही चुके हैं।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र के आसपास 'ईरान नीति' में बार-बार बदलाव की मांग करते हैं, जहां तेहरान ने इराक, लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन में सहयोगी लड़ाकों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाया है। आलोचक ईरान पर यह भी आरोप लगाते हैं कि वह बहरीन में सरकार विरोधियों का समर्थन कर रहा है। कोई और समय होता तो ट्रंप ऐसी मांगों पर नरम रुख अपनाते। लेकिन प्रशासन इस बार ऐसी मांगों को इनकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। बृहस्पतिवार को ही पेंटागन ने एक वीडियो जारी किया, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इसमें ईरानी नौसैनिक एक जहाज से बिना उपयोग किया गया विस्फोटक हटा रहे हैं, जिससे लगता है कि ईरान ने ही उसे वहां लगाया था और अब वह सबूत मिटाने का प्रयास कर रहा है। ईरान का कहना है कि यह सबूत जानबूझकर वहां प्लांट किया गया है। आखिर वह ऐसे हमला क्यों करेगा?

अनेक विशेषज्ञ ट्रंप प्रशासन के ईरान को जिम्मेदार ठहराने के दावे पर सवाल कर रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों में यह सहमति उभरी है कि पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के पोर्ट ऑफ फुजैरा में इसी जलमार्ग पर चार टैंकरों पर ईरान ने ही हमला किया था, हालांकि इससे बहुत नुकसान नहीं हुआ।

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान झांसा देकर प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचते हुए वाशिंगटन को नुकसान पहुंचाने के रास्ते तलाश सकता है। खाड़ी में टैंकरों को नुकसान होने से तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे अमेरिका दंडित होगा और इससे ईरान को लाभ होगा क्योंकि तब वह तेल बेचकर अपना राजस्व बढ़ा सकता है। अमेरिका के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ईरान अक्सर अमेरिका पर अप्रत्यक्ष हमला कर दंडित होने से बच निकलता है। उदारण के लिए 2003 के हमले के बाद जब अमेरिका ने ईराक पर कब्जा किया था, उस समय वाशिंगटन को पता था कि ईरान शिया लड़ाकों को प्रशिक्षित कर रहा है और हथियार मुहैया करा रहा है, जिन्होंने अमेरिकी बलों पर हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी जवान मारे गए। उस समय ईरान यही कहता रहा कि लड़ाके अपने से लड़ाई कर रहे हैं और इस तरह वह प्रत्यक्ष टकराव से बच गया।

गिरीश कारनाड से जुड़ी यादें

उनमें उच्च स्तर की सामाजिक चेतना थी और अपने देश के प्रति गहरा प्रेम था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी देशभक्ति और एक्टिविज्म का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने निर्देश दिया था कि उनकी मौत के बाद उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से न की जाए।

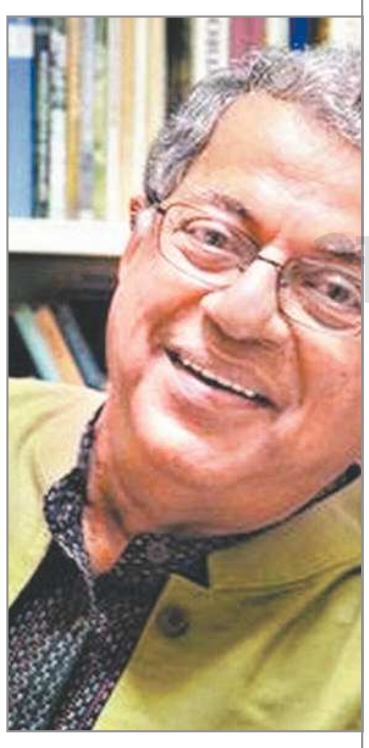

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

गिरीश कारनाड एक महामानव थे। पिछले हफ्ते बंगलूरू में सोते समय उनका निधन हो गया। कारनाड ने चार तरह का करियर चुना और वह उन सबमें उत्कृष्ट थे। वह तार्किक रूप से आजादी के बाद भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली नाटककार थे, जिनका रचनात्मक योगदान अपने विषयगत और लौकिक श्रेणी में आश्चर्यजनक रूप से व्यापक था। उन्होंने आधा दर्जन शानदार नाटक लिखे; इनमें राजनीतिक दृष्टांत *तुगलक*, सामाजिक सुधारवादी *तलेदंड* और गहरा हास्य व्यंग्य *ओदकलू बिम्ब* शामिल था। (मूलतः ये सभी कन्नड़ में लिखे गए और इनमें से सभी का आठवीं अनुसूची में शामिल प्रायः अधिकांश भाषाओं में प्रदर्शन हुआ)। वह एक असाधारण अभिनेता थे, जैसा कि श्याम बेनेगल की शुरुआती हिंदी फिल्मों में और पट्टाभिराम रेड्डी की कन्नड़ क्लासिक *संस्कार* में वह नजर आए थे। वह एक कुशल निर्देशक थे और उन्होंने के वी पुत्तप्पा और एस एल भाइरप्पा के प्रमुख उपन्यासों पर फिल्में बनाई। वह फिल्म ऐंड टेलीविजिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे (एफटीआईआई), संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली और नेहरू सेंटर, लंदन के काबिल प्रशासक थे। एफटीआईआई में उन्होंने अन्य लोगों के साथ ही नसीरूद्दीन शाह, ओम पुरी और टॉम आल्टर को तराशा।

एक बार मैं बंगलूरू से मुंबई जा रहा था। कारनाड भी उसी फ्लाइट में मुझसे कुछ आगे की पंक्ति पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा तो वह कागज के दस्ते पर पेन से कुछ कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वह अपने नए नाटक के मराठी अनुवाद का प्रूफ देख रहे हैं। कारनाड के प्रति मेरे मन में पहले ही बहुत सम्मान था और इसके बाद वह और बढ़ गया। एक शख्स जिसकी मातृभाषा कोंकणी थी और जो कन्नड़ में लिखता था, धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलता था और वह मराठी में भी पूरी तरह से सहज था।

कारनाड सिर्फ अनेक भाषाओं में दक्षता के कारण ही अन्य लेखकों और कलाकारों से अलग नहीं थे। मैं ऐसे किसी और शख्स को नहीं जानता, जो इतनी उदारता के साथ अपने शरीर और अपनी आत्मा में भारतीय सभ्यता को लेकर इतना समृद्ध और परिपूर्ण हो और वह भी खुद को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते बिना। अपने जीवन और काम में वह उत्तर और दक्षिण, लोक और शास्त्रीय, लोकगत और विद्धता में पूरी तरह से घुले मिले रहे। वह केसरबाई केरकर और मोहम्मद रफी के संगीत पर, बालासरस्वती और फराह खान के नृत्य पर तथा बासवा और आंबेडकर के नैतिक दर्शन पर बोलते हुए भी इसी तरह से काफी सहज रहते थे। वह शेक्सपीयर और फिलिप लार्किन की अंतर्दृष्टि पर भी बात कर सकते थे।

सितंबर, 2017 में जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब यह अफवाह उड़ी थी कि आतंकियों की हिट लिस्ट में अगले लेखक के रूप में गिरीश कारनाड हो सकते हैं। मैंने एक सुबह गिरीश को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या मैं दोपहर में उनसे मिल सकता हूं। मेरे घर से उनकी दूरी तय करने में एक घंटे लगते हैं और उनकी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए मैं उनसे मुलाकात के लिए अक्सर कई दिन पहले उन्हें मेल करता था। गिरीश ने अचानक आए मेरे फोन को सहजता से लिया और मुझे अपने घर बुलाया। मैं ड्राइव करता हुए निर्जन शहर को पार कर कारनाड के घर जेपी नगर पहुंचा। घर के बाहर लेखक की 'सुरक्षा' में तैनात वर्दीधारी गार्ड कुर्सी पर उनींदा बैठा हुआ था। जैसे ही मेरी कार वहां रुकी वह खड़ा हो गया और मुझे अंदर लेकर गया।

मैं वहां आधा घंटा बिताने के इरादे से गया था, लेकिन चार घंटे तक हम बात करते रहे। बेशक, हमने गौरी लंकेश के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बात की, जिसमें हमारे अपने जीवन के उतार-चढ़ाव भी शामिल थे। मैंने गिरीश से धारवाड़ के उनके शुरुआती दिनों के बारे में पूछा, तो उन्होंने देहरादून में मेरे बचपन के बारे में बात की। हम दोनों छोटे शहरों से महानगरों तक पहुंचे थे; बंगलूरू आने से पहले वह मुंबई गए थे और मैं दिल्ली। पहले बंगलूरू को हम एक कस्बे के तौर पर जानते थे और जब यहां हम रहने आए तो यह अच्छा खासा शहर बन चुका था। हमने अपने भाई-बहनों और ऐसे अन्य विषयों पर बात की जो अन्यथा हमारी साहित्यिक और बौद्धिक बातचीत का हिस्सा नहीं बनते। उनके भाई संगीतकार हैं, और मेरी बहन डॉक्टर हैं।

जब रात होने लगी तो मैं वापस जाने के लिए उठा। गिरीश चलकर मुझे मेरी कार तक छोड़ने आए। तब वहां सिक्योरिटी गॉर्ड कहीं नहीं था। गिरीश ने मुझे अचानक हुए मेरे प्रवास के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें और उनकी डॉक्टर पत्नी सारस को अच्छा लगा। मैंने कहा, 'मुझे लगता है कि एक ही शहर में रहने वाले दो लेखकों को एक-दूसरे की जरूरत तब पड़ी जब एक साथी लेखक की हत्या हो गई।'

सांस से संबंधित बीमारी के कारण कारनाड खुद भी काफी अस्वस्थ थे। उसके बाद आई जनवरी में वह धारवाड़ गए थे और वह जानते थे कि यह उस शहर की उनकी अंतिम यात्रा थी, जहां वह बड़े हुए, पढ़ाई की और अपने शुरुआती नाटक लिखे थे। उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मैं उनके साथ गया। इस तरह मुझे गिरीश कारनाड की अपने गृह नगर की अंतिम यात्रा में जाने का दुर्लभ अवसर मिला। लेकिन यह अवर्णनीय रूप से दुखी करने वाला था। धारवाड़ में सुभाष रोड पर स्थित लक्ष्मी भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं उनके साथ उनके लंबे समय तक प्रकाशक रहे मनोहर ग्रंथ माला के कार्यालय भी गया, जो वहां का उनका अंतिम प्रवास था।

कारनाड में उच्च स्तर की सामाजिक चेतना थी और अपने देश के प्रति उनमें गहरा प्रेम था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी देशभक्ति और एक्टिविज्म का प्रदर्शन नहीं किया। उनकी मर्यादा और उनकी सादगी ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने निर्देश दिया था कि उनकी मौत के बाद उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से न की जाए। वह जानते थे कि भांति-भांति के राजनेता वहां आना चाहेंगे और उनकी पार्थिव देह के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे और एक ऐसे शख्स के साथ खुद को जोड़कर अपना पाप धोने की कोशिश करेंगे जो कि महान कन्नड़ लेखक ही नहीं था, बल्कि अपने युग का महान कन्नदिगा (महान सपूत) भी था। अवसरवादियों और कट्टरपंथियों का साहस के साथ सामना करने वाले कारनाड को एक एक्टिविस्ट या पब्लिक इंटलैक्चुअल के रूप में देखना उन्हें पूरी तरह न समझ पाने और उनका कद कम करने जैसा है। इसके बजाय हमें उन्हें एक महान नाटककार, शानदार अभिनेता और एक गंभीर शिष्ट व्यक्ति के रूप में याद करना चाहिए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में उतना ज्ञान तो विस्मृत कर दिया होगा जितना कि भारतीय संस्कृति के आज के रक्षक जानते भी न हों।

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं

शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता दूर करने के लिए देश भर में एक समान पाठ्यक्रम के अलावा श्रम को महत्व देने, अध्यापन की शैली सुधारने और अध्यापक-अभिभावक संबंध को मजबूत करने की जरूरत है।

नई सरकार के आते ही नई शिक्षा नीति का मसौदा देश के सामने है। मसौदे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा तो की गई है, पर विजन, मिशन एवं उद्देश्यों में तारतम्य की कमी है। ऐसा लगता है कि विभिन्न एजेंसियों से जो टिप्पणियां आईं, उनको समन्वयक ने बस एक साथ रख दिया है। त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध दक्षिण भारत एवं पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऐसा लगता है कि जनता एवं उनके नुमाइंदे भाषा में ही उलझ गए। जबकि इसके बजाय जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, खासकर इंटरमीडिएट स्तर तक, किस तरह चल रही है और शिक्षा प्रणाली में किस तरह सुधार लाया जा सकता है, जिससे कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को उचित शिक्षा मिले, इस ओर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।

महीपाल

ज्योतिबा फुले का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो मस्तिक को सशक्त कर, नैतिक मूल्यों को खत्म किए बिना उसे उसके परंपरागत धंधों से बाहर निकलकर पैसा कमाने योग्य बनाए। शिक्षा ऐसी हो, जो जाति व्यवस्था पर प्रहार कर उसमें फंसी विभिन्न जातियों के लोगों को गतिशील करे। इसमें दोराय नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, शिक्षा को संविधान का अंग और 2009 में संविधान में सशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। देश में साक्षरता बढ़ी है। लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही। इस तरह के स्कूलों में न पर्याप्त अध्यापक हैं, न जरूरी संरचनात्मक सुविधाएं। इस तरह की व्यवस्था को अति शुद्र वाली शिक्षा व्यवस्था कहेंगे। सरकारी मॉडल स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सामान्य सरकारी स्कूल से ज्यादा सुविधाएं हैं और वहां अध्यापक भी अधिक हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को शुद्रवादी शिक्षा व्यवस्था कहेंगे। नगर पंचायतों या बड़े गांवों के पब्लिक स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं भी हैं और अध्यापक भी होते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था को वैश्य वाली शिक्षा व्यवस्था कहेंगे। शहरों के पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं और वहां अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होता है। इस तरह की शिक्षा को क्षत्रियवादी शिक्षा व्यवस्था कहेंगे। बड़े-बड़े नगरों के पब्लिक स्कूलों में वे तमाम सुविधाएं होती है, जो शिक्षा के लिए जरूरी हैं। इस व्यवस्था को ब्राह्मणवादी शिक्षा कहेंगे।

यह शिक्षा व्यवस्था न तो समान अवसर प्रदान करती है, न सभी को बराबर की हिस्सेदारी देती है। गांव के अतिशुद्ध और शुद्र समाज (जो या तो किसान/कारीगर व मजदूर हैं) के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। वैश्वीकरण के इस दौर में जिसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, वह आगे बढ़ेगा और जिसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वह या तो चौकीदार बनेगा या चाट-पकौड़े बेचेगा। इस असमान शिक्षा व्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला यह कि वर्तमान में हिंदी को लेकर कुछ राज्यों में परेशानी है। ऐसे में, त्रिभाषा फॉर्मूले की जगह द्विभाषा फॉर्मूला हो, पर हिंदी व अन्य भाषाएं वैकल्पिक रूप से हों, जिन्हें बच्चा खेल-खेल में सीखे। इससे वर्तमान में अंग्रेजी भाषा की जगह, जो विभिन्न राज्यों में संवाद की भाषा है, अन्य भाषाएं हो सकेंगी।

दूसरा सुझाव यह कि सभी जगह एक तरह की वर्दी व एक तरह की प्रार्थना होनी चाहिए। इससे बच्चों में देश की एकता एवं अखंडता के बारे में प्रवति बढ़ेगी। तीसरा सुझाव यह कि स्कूलों में एक ही तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग पाठ्यक्रम होने पर सभी बच्चों को एक तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसी तरह अध्यापकों के लिए भी एक तरह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। चौथा, गांव एवं नगरों में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे छह से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में भर्ती कराएं। पांचवें, चिकित्सा शिक्षा की तरह सामान्य शिक्षा भी व्यावहारिकता पर आधारित होनी चाहिए। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षार्थी बुकर टी वाशिंगटन ने शिक्षा की व्यावहारिकता को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने 'ट्रिपल एच' अर्थात हैंड, हेड, एवं हार्ट का उदाहरण देकर बताया था कि बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह बच्चों के हाथों, दिमाग एवं हृदय, तीनों का विकास करे। जो बच्चों गरीब परिवारों से हैं, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए कि वे पढ़ते समय कुछ कमाई करें, जिससे उनकी फीस एवं पढ़ाई के अन्य खर्च भी पुरे होते रहें। वाशिंगटन द्वारा चलाए गए स्कूलों में बच्चों से विभिन्न शारीरिक कार्य कराए गए। इस तरह का उदाहरण एक प्रयोग के रूप में अपनाया जा सकता है, जिसे बाद में बृहद स्तर पर लागू किया जा सकता है। और छठा सुझाव यह कि अध्यापक एवं अभिभावकों का संबंध स्थापित करने वाली पीटीएम (पैरेंट-टीचर मीटिंग) व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने की जरूरत है। अध्ययन बताते हैं कि जहां पर पीटीएम प्रभावी रही है, वहां पर छात्रों का विकास अधिक हुआ है।

शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षमता के विकास पर ध्यान देना जरूरी है। इस संदर्भ में चौदह राज्यों के 'ब्लॉक रिसोर्स सेंटर', एवं 'कलस्टर्स रिसोर्स सेंटर' का अध्ययन बताता है कि इन राज्यों में अध्यापकों के पास जरूरत से ज्यादा काम है, उचित शिक्षा संरचना की कमी है, समन्वयक उचित तरह से प्रशिक्षित नहीं है, यातायात के साधनों की कमी है, अध्ययन में नवाचार की कमी है। अतः अध्यापकों की कमी को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए एवं उसमें विभिन्न सुधार लाने के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना एक वैकल्पिक नीतिगत सुझाव प्रतीत होता है।